

वह मारकेट में आता है, अतः तेल निकालने की जो व्यवस्था है उस सब का रेगुलेट करने की आवश्यकता है आज सब कारखानों में जो कि प्राइवेट सैक्टर में हैं, मिलावट होती है और इस प्रकार लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसको सख्ती से रोकना चाहिए। यह तभी रोक सकते हैं जब आल सीड्स के कारखाने को आपरेटिव और पब्लिक सैक्टर में हों।

प्राइवेट सैक्टर के हर कारखाने में मिलावट हो रही है, यहां तक कि रंग देने के लिए भी मिलावट करते हैं। आपने कानून बना रखा है मिलावट रोकने के लिये, लेकिन उसका कितना असर होता है यह आप स्वयं जानते हैं। जो मिल मालिक करोड़ों रु० नाजायज तरीके से कमाते हैं मिलावट करके उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। जो करोड़ों रुपया मिलावट करके लोग कमा चुके हैं इसको रोकना चाहिए ताकि लोगों को खाने पीने का सामान सस्ता और साफ मिल सके। अन्यथा लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। मेरी तो राय यह है कि मिलावट करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए अगर आप आयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी मारकेटिंग के सम्बंध में तथा तेल निकालने के संबंध में आपको रेगुलेट करना पड़ेगा जिससे लोगों को अच्छा सामान उपलब्ध हो सके।

अंग्रेजों के समय में हम लोग बाहर से तेल नहीं मंगाते थे, मगर आज धीरे-धीरे लोगों ने खेती का पैटर्न बदल दिया जिसकी वजह से आयल सीड्स प्रोडक्शन में कमी आ गई है। अतः उस कमी को दूर करना चाहिए और यह तभी संभव है जब काश्तकार को इंसेटिव दिया जाएगा, आपको उनको इम्पुट्स रास्ते देने पड़ेंगे।

अभी हमारे श्री राजेश पाइलट ने नियम 377 का उल्लेख करते हुए यह बात कही है कि काश्तकारों की इलैक्ट्रीसिटी के दाम बढ़ाये जा रहे हैं, जमीन का लगान बढ़ाया जा रहा है, सिंचाई की दरें बढ़ायी जा रही हैं। इस तरह की दरें निश्चित तरीके से नहीं बढ़नी चाहियें। अगर आप काश्तकार को इंसेटिव देना चाहते हैं तो इस प्रकार के इम्पुट्स फार्मर को मिलने चाहियें जिससे वे ज्यादा आयल सीड्स पैदा कर सकें, उनका उत्पादन बढ़ा सकें और इनकी कमी को पूरा कर सकें। यह व्यवस्था आवश्यक है और इसको पूरा किया जाना चाहिए।

16.50 hrs.

STATEMENT RE. VISIT OF
FOREIGN MINISTER OF INDIA
TO SRI LANKA

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): I am sorry to interrupt the hon. Member. But I have a very brief statement to make.

Yesterday there was a long discussion here on the situation in Sri Lanka and just now the discussion in the Rajya Sabha has finished. In fact, as the Foreign Minister was replying to the discussion, I was on the telephone with the President of Sri Lanka, expressing the grave concern on behalf of the Members of Parliament and the people generally all over India, and especially the people of Tamilnadu and the South.

I suggested to the President that our Foreign Minister might go to Colombo to meet him. I am glad to say that he has agreed to this proposal. The Foreign Minister will leave this evening.

I also mentioned that we had heard of the shortage of essential supplies in the refugee camps and suggested that either we could approach the International Red

[Shrimati Indira Gandhi]

Cross which gives very effective assistance in such situations. We would also be willing to help through our own or other voluntary agencies. In reply to that, the President said, 'Let your Foreign Minister come and see things for himself and I will discuss with him.'

I thought I should let the House know.

NATIONAL OILSEEDS AND VEGETABLE OILS DEVELOPMENT BOARD BILL

AND

VEGETABLE OILS CESS BILL—Contd.

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल व्यास अपनी बात पूरी करें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह तो खत्म करके बैठ गये थे, फिर आपने उन्हें शुरू करवा दिया ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अच्छा मजाक कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : व्यास जी आप वाइंड-अप करें ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं निवेदन कर रहा था कि जब तक यह इम्पुट्स काश्तकारों को सस्ते भाव पर उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता । बड़े बड़े बोर्ड बनाना, बड़े-बड़े अधिकारियों, व्यूरोक्रेट्स की लम्बी चौड़ी फौज कायम करना कोई मायने नहीं रखता ।

हार्वेस्ट के टाइम पर चीजें सस्ती हो जाती हैं और उसके बाद किसान के हाथ से जब चीजें निकल जाती हैं और व्यापारियों के पास चली जाती हैं तो वह बहुत मंहगी हो जाती है । वह लोग मनमाने तरीके से पैसे वसूल करते हैं और लोगों को सामान मंहगा

मिलता है । इसके साथ सट्टे भी चलते हैं एक-एक साल पहले सट्टा लगा दिया जाता है कि किस भाव पर तिलहन को खरीदा जाएगा । इस प्रकार की व्यवस्था को रोकना चाहिए । यह लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है । इसको अगर हम नहीं रोकेंगे तो तेल और मंहगे भाव पर लोगों को मिलेंगे, वह कभी सस्ते नहीं हो पायेंगे । इन स्पैकुलेटिव व्यवस्थाओं को रोकने की आवश्यकता है । जैसे सरकार गेहूं खरीदती है, तिलहन भी वह खरीदे । आप व्यापारियों के जरिए क्यों तिलहन खरीदना चाहते हैं ? जब 600,700 करोड़ रुपये सरकार को तिलहन के लिये खर्च करने पड़ते हैं तो इस ट्रेड को सरकार हाथ में लेकर क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करना चाहती जिससे सस्ते भाव पर लोगों को तिलहन मिल सके ?

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि टैक्नीकल एजुकेशन भी दी जानी चाहिए । मेरा कहना कि काश्तकारों को इस बात की जानकारी दीजिए कि कौनसे इलाके में कौनसी चीजें पैदा हो सकती हैं । अगर काश्तकारों को यह शिक्षा नहीं दी जाएगी कि रेत की जमीन में, काली मिट्टी में या लाल मिट्टी में कौनसा तिलहन ज्यादा पैदा हो सकता है, तो वे लोग अपनी मर्जी से तिलहन बो देंगे, जिससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा । इस लिए काश्तकारों को यह शिक्षा देना नितांत आवश्यक है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी चीज बोने से उत्पादन ज्यादा होगा और देश को ज्यादा लाभ होगा ।

इस कानून के साथ ही एक सेस का कानून भी लाया गया है । हस्तारे यहां खास तौर से माइका, सोप-स्टोन और आयरन और आदि खानों के प्रोडक्शन पर जितने